

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जून, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत हरिद्वार/ऋषिकेश जलोत्सारण योजना के रखरखाव हेतु कराये गये कार्यों के सम्बंध में धनावटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 126/न0यो0अनु0/छळत्त।/4 दिनांक 22.01.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वित्तीय वर्ष 2010-11 में हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव हेतु प्रस्तुत अनु0 लागत ₹ 1732.28 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹ 1457.54 लाख (₹ चौदह करोड़ सत्तावन लाख चवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 600.00 लाख (₹ छः करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.2012 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्टाफ, विद्युत, डीजल एवं अन्य मदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता आधार पर उक्त अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.12.2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

6- कराये जाने वाले कार्यों पर सेन्टेज प्रभार अनुमन्य नहीं होगा उल्लेखनीय है कि संचालन, स्टाफ, वेतन, अतिरिक्त स्टाफ आदि मदों की धनराशि प्रस्तुत आगणन में ही सम्मिलित है तथा कार्य संचालन/रखरखाव का है।

7- व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु निगम के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

10- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

11- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत

कमश:.....2



/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

13— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

14— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

15— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

16— व्यय अनुमोदित लागत की समीक्षित ही सीमित किया जाय तथा न्यूनतम आवश्यकता आधार पर यदि कोई बचत होती है तो उसे राजकोष में जमा किया जाय। सीवर चार्ज आदि से प्राप्त राजस्व की धनराशि के समतुल्य धनराशि भी राजकोष में जका करा दी जाये।

17— चूंकि दिनांक 01.04.2011 से संचालन/रखरखाव का कार्य जल संस्थान को हस्तान्तरित हो गया है। अतः स्वीकृत आगणन/धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल सृजित देनदारियों के भुगतान हेतु ही किया जाय। साथ ही विगत वर्षों जिस अवधि में संचालन/रखरखाव निगम पर रहा है, के सापेक्ष सीवर चार्ज आदि मदों में लम्बित राजस्व वसूली के विवरण जल संस्थान को उपलब्ध करा दिये जाय ताकि उनके स्तर पर वसूली की कार्यवाही की जा सके।

18— रखरखाव तथा मशीनों पर व्यय नियमानुसार एवं स्वीकृत मानको के आधार पर किया जाय।

19— उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मल निकासी एवं सफाई- आयोजनागत -106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-03-गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज-1 एवं II)- 00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

20— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-161/XXVII(2)/2011 दिनांक 02 जून 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

पू0सं0 109(i)/उन्तीस(2)/11-2(70पे0)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन/राज्य योजना आयोग/बजट सेल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)  
उप सचिव